



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

५७/१९९८

८०

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 217]

नई दिल्ली, बुहस्यतिवार, अक्टूबर 8, 1998/आश्विन 16, 1920
No. 217] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 1998/ASVINA 16, 1920

वित्त मंत्रालय

में

(राजस्व विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1998

फ्र. सं. 24/45/98-वि.क्र.—14 सितम्बर, 1998 को हुए मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में संकल्प लिया गया था जिसमें विक्री कर को युक्ति-युक्त बनाने, मूल्य-वर्धित कर (वी. ए. टी.) शुरू करने और पिछड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए मुख्य मंत्रियों की एक समिति गठित करने की सिफारिश की गई थी।

2. इस संकल्प के अनुसरण में, भारत सरकार ने मिन्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है :

1. मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
2. मुख्यमंत्री, गुजरात
3. मुख्यमंत्री, हरियाणा
4. मुख्यमंत्री, उड़ीसा
5. मुख्यमंत्री, कर्नाटक
6. मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश
7. डॉ. राजा जे. घरैया

एन. आई. पी.एफ. एंड पी., नई दिल्ली, को संयोजक के रूप

8. डॉ. महेश सी. पुरोहित

एन.आई.पी.एफ. एंड पी., नई दिल्ली, को सचिव के रूप में।

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

- (क) विक्री कर के लिए एक-समान व्यूनतम दरों के लिए कार्यान्वयन अनुसूची तैयार करना,
- (ख) विक्री-कर पर आधारित प्रोत्साहन योजनाओं का समाप्त करने की सिफारिश करना,
- (ग) पिछड़े क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए पद्धति तैयार करना जो प्रोत्साहन योजनाओं के लिए पात्र हो सकते हैं, ऐसे प्रोत्साहनों की अधिकतम मात्रा और इसकी मानीटरिंग के लिए तंत्र, और
- (घ) मूल्य-वर्धित कर शुरू करने और केन्द्रीय विक्री कर (सीएसटी) की कटौती के लिए समय-सीमा का सुझाव देना।

4. समिति अपने कार्य और जांच के लिए स्वयं की कार्य-पद्धति और विधि तैयार करेगी, यह केन्द्र सरकार तथा राज्य/संघ शासित सरकारों से जरूरत होने पर सूचना मांग सकती है।

5. अपर सचिव (प्रशासन), राजस्व विभाग भी समिति की बैठकों में भाग लेंगे, जब उन्हें भारत सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में बुलाया जाएगा। एन. आई. पी. एफ. एंड पी., नई दिल्ली, समिति को सचिवालीय सहायता प्रदान करेगा।

6. समिति अपनी रिपोर्ट 15 नवंबर, 1998 तक प्रस्तुत करेगी।
 जी. सी. श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

RESOLUTION

New Delhi, the 8th October, 1998

F. No. 24/45/98-ST.—The Conference of Chief Ministers' and Finance Ministers' held on the 14th September, 1998 had adopted a resolution recommending constitution of a Committee of Chief Ministers to go into the issue concerning rationalization of sales tax, introduction of Value Added Tax (VAT) and incentives to backward areas.

2. In pursuance of this resolution, the Government of India has decided to appoint a Committee consisting of the following :

1. Chief Minister of West Bengal
2. Chief Minister of Gujarat
3. Chief Minister of Haryana
4. Chief Minister of Orissa
5. Chief Minister of Karnataka
6. Chief Minister of Arunachal Pradesh
7. Dr. Raja J. Chelliah,
 NIPF&P, New Delhi as Convenor
8. Dr. Mahesh C. Purohit
 NIPF&P, New Delhi as Secretary.

3. The terms of reference of the committee will be—
 - (a) To formulate an implementation schedule for uniform floor rates for sales tax;
 - (b) To recommend phasing out of sales tax based incentive schemes;
 - (c) To formulate the criteria for defining backward areas that may be eligible for incentive schemes; the maximum quantum of such incentives and the mechanism for its monitoring ; and
 - (d) To suggest a time frame for introduction of VAT and for reduction of CST.
4. The committee will evolve its own procedures and methods for its work and study; it may call for information as may be necessary from Central and State/U.T. Governments.
5. The Additional Secretary (Administration), Department of Revenue, will also attend the meetings of the Committee, when concerned as a representative of the Government of India. The NIPF&P, New Delhi will provide secretarial assistance to the Committee.
6. The Committee will submit its report by 15th November, 1998.

G.C. SRIVASTAVA, Addl. Secy.